जानवरों का शिकार

1403. **श्री रामदेव भंडारी:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 जुलाई, 1996 के "नवभारत टाइम्स" में "अमीरों का मनोरंजन, जानवरों का सफाया" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, यदि हां, तो इस समाचार का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार में शिकारियों द्वारा मारे जा रहे वन्य-जन्तुओं की सुरक्षा हेतु क्या कार्रवाई कर रही है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद): (क) जी, हां। यह खबर उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर अभयारण्य की सीमा, इसकी कानूनी अवस्थिति, अलीगढ़ मुस्लिम विश्व विद्यालय द्वारा किए गए सर्वेक्षण के निष्कर्षों, प्रभावी व्यक्तियों द्वारा अवैध शिकार की समस्या, झाबर मृग सहित वन्यजीव-जन्तुओं को बिजली का करंट लगा कर मारने, भूमि के अवैध कब्जे, घास और मछली का अवैध नीलाम तथा अभ्यारण्य के प्रबंधन के लिए अपर्याप्त और असुसज्जित फील्ड स्टाफ के बारे में है।

(ख) मुख्य वन्यजीव वार्डन ने खबर दी है कि फील्ड स्टाफ द्वारा नियमित रूप से गस्त लगायी जा रही है और अवैध शिकार को रोकने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं जिसे 1995-96 में काफी हद तक नियंत्रित किया गया है।

अभयारण्य के वास्तविक ब्यौरे तथा की गई कार्रवाई में हैं:—

हस्तिनापुर अभयारण्य में उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मुरादाबाद और बिजनौर जिलों का 2073 वर्ग कि०मी० का क्षेत्र आता है। इसका 186.26 वर्ग कि०मी० क्षेत्र ही राज्य वन और वन्यजीव विभाग के नियंत्रणाधीन है और शेष वनेतर क्षेत्र है जिसमें काफी लोगों की आबादी और खेती है। राज्य मुख्य वन्यजीव वार्डन ने खबर दी है कि सिंचाई विभाग के डूब क्षेत्र जो अभयारण्य का हिस्सा है, में स्थानीय पंचायत द्वारा मछलियों, घास आदि की नीलामी की जाती है जिसके लिए राज्य मुख्य वन्यजीव वार्डन ने आपत्ति की है। अपर्याप्त और असुसज्जित फील्ड स्टाफ के साथ-साथ ये मसले अभयारण्य के वनेतर भूमि में वन्यजीव-जन्तुओं की सुरक्षा के लिए समस्या बन रहे हैं। मुख्य वन्यजीव वार्डन ने यह भी खबर दी है कि 1995-96 के दौरान अपराध के 62 मामलों का पता लगाया गया जिनमें से 9 मामले न्यायालयों को भेजे गए। केवल 2 मामले ही वन्यजीव-जन्तुओं के अवैध शिकार किए जाने से संबंधित है और झाबर मृग के अवैध शिकार की कोई खबर नहीं है।

Rise in Subsidy of Chemical Fertilizers

1404. SHRI PARAG CHALIHA:
SHRI GOVINDRAM MIRI:

Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) what will be the total increase per annum due to recent rise in subsidy rates on chemical fertilizers; and

(b) what is the justification, if any, of this rise?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI SHEES RAM OLA): (a) On account of increase in the rates of special concession on decontrolled phosphatic and potassic fertilizers, the provision of Rs. 500 crore made in the interim budget for 1996-97 has been revised to Rs. 2224 crores.

(b) The rates of special concession have been enhanced with a view to making these fertilizers available to farmers at reasonable prices so as to increase their consumption and improve the N.P.K. ratio.

राष्ट्रीय नदी कार्य योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव

1405. **श्री राधाकिशन मालवीय:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1993—96 के दौरान राष्ट्रीय नदी कार्य योजना के अन्तर्गत सरकार को कितने राज्यों से कौन-कौन सी नदियों के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) योजनाओं के नाम तथा उनमें से प्रत्येक के लिए आवंटित धनराशि के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार चालू वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश से प्राप्त योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कोई धनराशि आवंटित करेगी; और

(घ) यदि हां, तो आवंटन धनराशि कितनी है तथा यह धनराशि कब तक आवंटित किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद): (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने 10 राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों (व्यवहार्यता रिपोर्ट) के आधार पर राष्ट्रीय नदी संरक्षण योनजा का अनुमोदन किया है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत नदियों के नाम और विभिन्न स्कीमों की अनुमोदित राशि का विवरण अनुपत्र में दिया गया है। **[देखिए परिशिष्ट 178, अनुपत्र संख्या 37क]**

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार ने चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में कार्यों के कार्यान्वयन के लिए 2.00 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन किया है।

Cancellation of Trains in Trivandrum Division

1406. SHRI THENNALA BALAKRISHNA PILLAI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some trains are being cancelled due to non-availability of rail coaches in the Trivandrum Division of Southern Railways;

(b) if so, what is the reason for non-availability of rail coaches; and

(c) what steps are being taken to overcome that?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SATPAL MAHARAJ): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

Schools in Punjab

1407. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what is the, District-wise, number of Central Schools and Navodaya Vidyalayas opened in the State of Punjab during the last three years; and

(b) the, District-wise, details of such schools proposed to be opened in the State, during the year 1996-97?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MUHI RAM SAIKIA): (a) One Navodaya Vidyalaya has been opened in the District Bhatinda, while no Kendriya Vidyalaya has been opened, in Punjab, during the last 3 years.

(b) At present there is no proposal to open a Navodaya/Kendriya Vidyalaya in Punjab during 1996-97.

Projects pending for Environment clearance

1408. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the Minister of ENVIRONEMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) the numbers of power, steel and other industrial projects pending for environmental clearance;

(b) since when these projects are pending; and

(c) the steps taken to expedite the clearance of these projects?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (CAPT. JAI NARAIN PRASAD NISHAD): (a) and (b) One hundred thirty eighth projects (35 Thermal Power, 1 Hydro Power, 8 Steel and 94 other industrial projects) are pending for environmental clearance as on 15th July, 1996 and are pending from August, 1994 to July, 1996.